संपादकीय जागरण

मंगलवार, 12 दिसंबर, 2017 : पौष कृष्ण 10 वि. 2074

हृदय और मस्तिष्क का मेल ही किसी प्रयोजन को पूर्ण कर सकता है

एक हाथ से नहीं बजेगी ताली

चुनावों के वक्त किस तरह छोटे-बड़े, जरूरी-गैर जरूरी या फिर ठोस-सतही मसले उछलने शुरू हो जाते हैं, इसका ही प्रमाण इन दिनों गुजरात चुनाव में मिल रहा है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किए गए उस राजनीतिक हमले का सामना करने के लिए तैयार नहीं थी जिसके तहत उन्होंने कांग्रेसी नेताओं की पाकिस्तानी राजनयिकों के साथ बैठक का जिक्र करके उसे घेरा। पहले तो कांग्रेसी नेताओं ने ऐसी किसी बैठक को आधारहीन बता दिया, लेकिन जब यह सामने आया कि मणिशंकर अय्यर के घर पर ऐसी एक बैठक वास्तव में हुई थी तो फिर उन्हें इसकी स्वीकारोक्ति करनी पड़ी। इससे उस प्रसंग की याद ताजा हो गई जिसके तहत डोकलाम विवाद के समय राहुल गांधी की चीनी राजदूत से मुलाकत का पहले खंडन किया गया था और फिर स्वीकारोक्ति। कांग्रेसी नेताओं की यह सफाई सही हो सकती है कि उक्त बैठक गोपनीय नहीं थी और उसमें गुजरात चुनाव नहीं, केवल दोनों देशों के संबंधों पर चर्चा हुई थी, लेकिन उन्हें यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि प्रधानमंत्री ने इस बैठक को लेकर जो संदेह जताया उस पर खेद जताएं। साफ-सुथरी राजनीति की जिम्मेदारी किसी एक पक्ष पर नहीं डाली जा सकती और तब तो बिल्कुल भी नहीं जब दूसरा पक्ष ऐसा करने से साफ इन्कार कर रहा हो। ताली एक हाथ से नहीं बजती। अगर राहुल गांधी जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स करार देने के साथ यह भी कहते रह सकते हैं कि मोदी सरकार तो बस चार-छह उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है तो फिर वह यह उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि उनके लोगों को ऐसे ही आरोपों का सामना नहीं करना पड़ेगा?

आखिर कांग्रेस किस आधार पर प्रधानमंत्री के आरोप पर आगबबूला हो रही है? क्या वह यह कहना चाहती है कि उसके नेताओं को तो हर तरह के उचित-अनुचित आरोप लगाने का अधिकार है, लेकिन ऐसा कोई अधिकार विरोधी पक्ष को नहीं मिल सकता? निःसंदेह ऐसा भी नहीं है कि गुजरात में उसका चुनाव प्रचार राजनीतिक गरिमा के सर्वथा अनुकूल हो। सच यह है कि सबसे पहले उसी ने विकास को पागल करार देने का काम किया था। पहले उसने विकास को पागल, बद्तमीज वगैरह करार दिया और फिर यह सवाल पूछना शुरू किया कि आखिर भाजपा विकास की बात क्यों नहीं कर रही है? राजनीति में और खासकर चुनाव प्रचार के दौरान कोई किसी से पीछे नहीं रहना चाहता। दरअसल इसी कारण चुनाव आते ही तू तू-मैं मैं शुरू हो जाती है और कई सतही मसले भी सतह पर आ जाते हैं। ऐसा न हो, इसके लिए सभी राजनीतिक दलों को गंभीरता का परिचय देना होगा। दुर्भाग्य यह है कि कोई भी दल ऐसा नहीं जो चुनाव लड़ते समय राजनीतिक शुचिता के प्रति सजग नजर आता हो। स्थिति कितनी खराब हो चुकी है, यह इससे समझा जा सकता है कि कई राजनीतिक दल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को संदिग्ध बताने के लिए हर तरह के झूठ और छल का सहारा लेने को तो तैयार हैं ही, यह साबित करने की भी कोशिश में हैं कि केंद्रीय सत्ता और केंद्रीय निर्वाचन आयोग में साठगांठ भी है।

मानवता कलंकित

राजधानी लखनऊ के सरोजनीनगर क्षेत्र में ब्लड कैंसर से पीड़ित एक किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म की घटना मानवता पर ऐसा कलंक है जिसके दाग कभी नहीं धुल सकते। ऐसी घटनाएं यह सोचने को विवश करती हैं कि आखिर हम किस समाज में रह रहे हैं, जहां विश्वास और भरोसे का भी पूरी बर्बरता से दम घोंट दिया जाता है। जिस किशोरी से दुराचार हुआ उसने दो युवकों से इस उम्मीद में मदद मांगी थी कि वह उसे सुरक्षित घर तक पहुंचा देंगे, लेकिन उन्होंने धोखेबाजी की। यही नहीं कुछ देर बाद उसने जिस दूसरे व्यक्ति पर भरोसा किया, उसने भी उसकी मजबूरी का फायदा उठाया। अब हम कैसे यह दावा कर सकते हैं कि सभ्य समाज में जी रहे हैं। कोई एक घटना हो तो उसे विकृति की संज्ञा दी जा सकती है, लेकिन यहां तो इसी तरह की एक घटना बाराबंकी में भी हुई जहां मानसिक मंद युवती से दुष्कर्म किया गया। ऐसी ही घटना राजधानी में भी हो चुकी है।

ऐसा अपराध करने वालों को कानून की धाराओं के तहत इतनी कड़ी सजा मिलनी चाहिए जो समाज में एक सबक की तरह दिखाई दे

भरोसे का यह संकट समाज में बढ़ता ही जा रहा है। फैजाबाद में अपनी आठ साल की बच्ची को स्कूल पहुंचाने के लिए एक परिवार ने जिस वाहन चालक पर भरोसा किया, उसने ही उसे अपनी हवस का शिकार बनाया। सीतापुर में एक विवाहिता ने जिस दंपती पर भरोसा जताया, उसी ने पचास हजार में उसका सौदा कर लिया। ऐसी कई घटनाएं हैं जो विश्वास का खून करती हैं। कानून के नजरिये से देखें तो इस तरह का अपराध करने वाले किसी भी तरह की रहम के पात्र नहीं हैं। उनको कानून की धाराओं के तहत इतनी कड़ी सजा मिलनी चाहिए जो समाज में एक सबक की तरह दिखाई दे।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या अमेरिका द्वारा यरुशलम को इजरायल की राजधानी के रूप में मान्यता देने से वैश्विक स्तर पर अशांति बढ़ेगी?

आज का सवाल

क्या राहुल गांधी ने राजनीतिक रूप से परिपक्व नेता की छवि हासिल कर ली है?

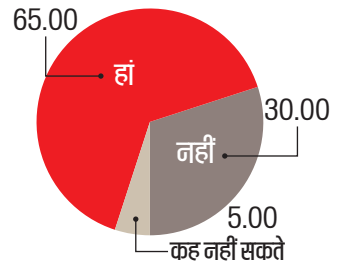

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर **POLL** लिखें, स्पेस देकर **Y, N** या **C** लिखकर 57272 पर भेजें
Y -हां, **N**-नहीं, **C**-कह नहीं सकते

परिणाम एसएमएस से प्राप्त नतीजों के साथ जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

विकास को पागल बताने वाली राजनीति

अभिनव प्रकाश

चुनावी लाभ के लिए आंकड़ों को गलत तरीके से पेशकर गुजरात की दूसरी तस्वीर खींचना नकारात्मक राजनीति का चरम ही है

पिछले 22 वर्षों से गुजरात की सत्ता पर काबिज भाजपा राज्य की जनता से एक बार फिर जनादेश की गुहार लगा रही है तो इतने लंबे अरसे से सत्ता से बाहर रही कांग्रेस को वापसी का सुनहरा मौका नजर आ रहा है। दिलचस्प यह है कि अमूमन रक्षात्मक रहने वाली कांग्रेस इस बार खासे आक्रामक तेवर दिखा रही है और भाजपा को उसी के हथियार से मात देने की फिराक में है। यह हथियार और कुछ नहीं विकास का वही 'गुजरात मॉडल' है जिसके दम पर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के पद तक पहुंच गए। अब कांग्रेस के निशाने पर यही गुजरात मॉडल है। उसका आरोप है कि गुजरात में कोई विकास हुआ ही नहीं। प्रथमदृष्टया उसका यह आरोप हैरान करता है, क्योंकि हाल तक कांग्रेसी यह कहते नहीं थकते थे, 'मोदी ने किया ही क्या है? गुजरात तो पहले से ही विकसित था!' मोदी के गुजरात मॉडल का पहला स्तंभ राज्य और कानून-व्यवस्था से जुड़ा है जिसमें कानून के राज को आदर्श रूप से स्थापित किया गया। कांग्रेसी शासन में दंगा-राज और गुंडा-राज ही गुजरात का यथार्थ था। राजनीतिक सत्ता का सारा खेल जाति और मजहब के गुणा-गणित पर आधारित था। सभी राजनीतिक दलों ने अपने-अपने पक्ष की जातियों के 'बाहुबलियों' को प्रश्रय देने की नीति अपना रखी थी। ये बाहुबली चुनाव के वक्त काम आते थे। इसके विपरीत गुजरात मॉडल के केंद्र में हिंदुत्व के आधार पर एक संयुक्त-हिंदू मतदाता वर्ग का निर्माण किया गया। संगठित हिंदू-वोट ने एक ही झटके में सारा पुराना चुनावी गुणा-गणित खत्म कर दिया।

गुजरात में पहले अन्य राज्यों की तरह से कोई भी पार्टी दो-तीन हिंदू जातियों को साधती थी और मुस्लिम वोटों को उसमें सम्मिलित करके चुनाव जीत जाती थी, परंतु इससे होता यह था कि सरकार हमेशा इन जातियों और समुदायों के नेताओं एवं गुंडों से ब्लैकमेल होती रहती थी। वह गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई का साहस इस भय से नहीं जुटा पाती थी कि कहीं उसकी कीमत अगले चुनाव में न चुकानी पड़ जाए। चूंकि मोदी का गुजरात इस दलदल से मुक्त हो सका इसीलिए वह संगठित अपराध, माफिया और बाहुबलियों के वर्चस्व को तोड़ने में सफल हुआ। जहां देश की राजधानी दिल्ली तक में बाजार 8-9 बजते-बजते बंद हो जाते हैं और थोड़ी बहुत नाइट्लाइफ पब-डिस्को और होटलों तक सिमट जाती है वहीं गुजरात के शहरों में आधी-रात तक सड़कों पर बाजार की रौनक रहती है और लोग सपरिवार घूमते दिखते हैं। इनमें लड़कियां और महिलाएं भी होती हैं। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार गुजरात महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित राज्यों में से है। जहां पहले शहरों के चुनिंदा इलाकों में 'भाई कल्चर' चलता था और महीनों तक कर्फ्यू लगा रहता था वहां अब बाजार फल-फूल रहे हैं। जाहिर है कि कानून एवं व्यवस्था अच्छी होगी, स्थायित्व और शांति होगी तो अर्थव्यवस्था भी बेहतर होगी ही। 2001-2013 से गुजरात की जीडीपी 10 फीसद की दर से बढ़ी है। यही नहीं 2012-2017 के कालखंड में भी जब हर जगह

विकास दर गिरी है तब भी गुजरात ने 10 प्रतिशत की दर बरकरार रखी है, जो देश में सबसे अधिक है। यह भी उल्लेखनीय है कि भारत का 22 प्रतिशत निर्यात गुजरात से होता है। 2013-2017 में गुजरात की अर्थव्यवस्था में औद्योगिक और उत्पादन क्षेत्र का हिस्सा 28.4 फीसद से बढ़ कर 34.4 फीसद हो गया है जो कि चीन के समकक्ष है। 1999-2000 में गुजरात अगर भारत का पांचवां सबसे समृद्ध राज्य था तो आज यह देश का तीसरा सबसे समृद्ध राज्य है।

'अंबानी-अडानी की सरकार' और कॉरपोरेट मॉडल के फर्जी प्रवचन के विपरीत गुजरात की अर्थव्यवस्था का 37 फीसद हिस्सा लघु और मध्यम उद्योगों का है और पिछले 5 वर्षों में सबसे अधिक बढ़त श्रम प्रधान क्षेत्रों में हुई है। देश में सबसे अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग गुजरात में हैं। गुजरात सबसे कम बेरोजगारी वाले क्षेत्रों में से है। दरअसल गुजरात आज पश्चिम बंगाल, बिहार, पूर्वी उत्तर-प्रदेश और अन्य इलाकों के मजदूरों के पलायन का मुख्य केंद्र है। रोजी-रोटी की तलाश में गुजरात जाने वालों में अमेठी और रायबरेली के लोग भी शामिल हैं। यहां के कई परिवार तो स्थाई रूप से वहीं बस गए हैं। सोशल सेक्टर में भी गुजरात की प्रगति सराहनीय है। आंकड़ों को गलत तरीके से पेश कर गुजरात की गलत तस्वीर खींची जा रही है। केरल में शिशु मृत्यु दर (12/1000) की गुजरात (33/1000) से तुलना करके यह बताया जा रहा है कि गुजरात में विकास के दावे झूठे है। जो नहीं बताया जा रहा वह यह कि 2001 में केरल में यह दर 11/1000 थी और गुजरात में 60/1000। केरल में यह 11 से बढ़ कर 12 हुई है तो गुजरात में 60 से घट कर 2015 में 33 हुई और 2017 में कुछ और कम।

गुजरात कम पानी वाला क्षेत्र है। यहां की बहुत सी जमीन बंजर है या फिर कम उपजाऊ है, फिर भी गुजरात कृषि क्षेत्र में 11 प्रतिशत तक की विकास दर हासिल करने में सक्षम रहा है। इजरायल की सिंचाई की आधुनिक तकनीक-ड्रिप-सिंचाई को अपनाने, 1,00,000 चेक-डैम बनाने, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, कृषि-बाजार में सुधार, किसानों को सूचना के साधनों और तकनीक से जोड़ने के जो काम किए गए उनके चलते हालात पहले से बेहतर हुए हैं। गुजरात मॉडल में आधारभूत संरचना में निवेश पर भी खासा जोर दिया गया है। बिजली-क्षेत्र में सुधार का गुजरात सफल उदाहरण है। इसके अलावा वह अक्षय ऊर्जा जैसे वायु और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी देश के अग्रणी राज्यों में से है। गुजरात सौ फीसद गांवों में बिजली पहुंचाने वाला पहला राज्य है। वह घरेलू उपभोक्ताओं को 24 घंटे और खेती-सिंचाई जैसे कार्यों के लिए प्रतिदिन 8-10 घंटे बिजली देने में सफल रहा है। सड़कों, बंदरगाहों इत्यादि में अप्रत्याशित सुधार की कहानी तो जगजाहिर है।

गुजरात मॉडल का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ प्रशासनिक सुधार है। मोदी ने गुजरात में न केवल पेशेवर लोगों की नियुक्ति पर जोर दिया, बल्कि नियुक्तियों और प्रोन्नति में कार्य-प्रदर्शन को अहमियत देना शुरू किया। इसके अलावा नई तकनीक खासतौर पर डिजिटल तकनीक को बड़े पैमाने पर सरकारी ढांचे में एकीकृत करना शुरू किया। इससे एक ओर जहां सरकार की कार्य-क्षमता बढ़ी वहीं दूसरी ओर भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगी। सीएमएस के 2017 के एक शोध के अनुसार कांग्रेस शासित कर्नाटक देश का सबसे भ्रष्ट राज्य है वहीं गुजरात में 2005-17 के बीच भ्रष्टाचार में गिरावट आई है। गुजरात मॉडल अच्छी कानून एवं व्यवस्था, कुशल प्रशासन, बेहतरीन आधारभूत ढांचे और उद्योग-व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अधिक से अधिक आर्थिक स्वतंत्रता देने पर आधारित है और इसी कारण वह लगातार दो दशकों तक 10 प्रतिशत की आर्थिक विकास दर देने में सफल रहा है। यह सही है कि सोशल सेक्टर में कई क्षेत्रों में बेहतर काम हो सकता था, लेकिन कांग्रेस का यह कहना कि 'विकास पागल हो गया है' नकारात्मक राजनीति का चरम है। बजाय इसके कि बेहतर काम करने का अपना मसौदा रखकर विपक्ष चुनाव लड़ता, वह जाति-समुदाय की राजनीति के आधार पर चुनाव लड़ रहा है। यह एक तरह से गुजरात को 80 और 90 के दशक में लौटाने वाली राजनीति है।

(लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के असिस्टेंट प्रोफेसर एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं)

response@jagran.com

अन्याय के आघात सहती आस्था

बलबीर पुंज

कुछ लोग अपने क्षुद्र स्वार्थ के लिए अयोध्या विवाद को अनंतकाल तक विवादित रखना चाहते हैं

राहुल गांधी जिस समय स्वयं को जनेऊधारी ब्राह्मण घोषित कराने के लिए आतुर दिख रहे थे, लगभग उसी समय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं अधिवक्ता कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में रामजन्मभूमि के विरुद्ध बहस कर रहे थे। अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने के 25 वर्ष पूरे होने से एक दिन पहले अदालत में जो तर्क सिब्बल ने प्रस्तुत किए उसमें भारत में सदियों से हिंदू-मुसलमानों के बीच चले आ रहे द्वेषभाव की विवेचना निहित है। उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता के रूप में कपिल सिब्बल ने न्यायालय से मांग करते हुए कहा, 'अयोध्या का मामला राजनीतिक हो चुका है, इसलिए 2019 में लोकसभा चुनाव के बाद इसकी सुनवाई की जाए।' ध्यान रहे कि 2010 में अयोध्या के संबंध में आए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका शीर्ष अदालत में गत सात वर्षों से लंबित है। क्या विलंब को और खींचना न्यायसंगत है? यूं तो स्वतंत्र भारत में यह मामला 1950 से न्यायालय में अटका है, किंतु इसका संपूर्ण कानूनी इतिहास 133 वर्ष पुराना है जब 29 जनवरी, 1885 को अंग्रेजी राज में पहली बार महंत रघुवर दास ने रामचबूतरे पर मंदिर निर्माण हेतु याचिका दाखिल की थी। इसे बाबरी मस्जिद के तत्कालीन संरक्षक मोहम्मद असगर से चुनौती मिली। उस समय फैजाबाद के उप-न्यायाधीश ने महंत की याचिका खारिज कर दी। 65 वर्ष पश्चात 23 दिसंबर, 1949 को न्यायिक हस्तक्षेप के बाद हिंदुओं को लोहे की जालीदार दीवार के पीछे से पूजा करने की स्वीकृति मिल गई।

जब रामजन्मभूमि मुक्ति आंदोलन गति पकड़ रहा था तभी 1985 में शाहबानो प्रकरण सामने आया। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने तलाकशुदा मुस्लिम पत्नी को उसके पूर्व पति से गुजारा भत्ता लेने का ऐतिहासिक निर्णय दिया, किंतु कट्टरपंथी मुसलमानों के दबाव और मुस्लिम वोट बैंक को साधने हेतु पूर्ण बहुमत वाली राजीव गांधी सरकार ने 1986 में संसद के भीतर न्यायालय का निर्णय पलट दिया और शरीयत के अनुरूप एक अधिनियम पारित कर दिया। 1989 के आम चुनाव को ध्यान में रखकर राजीव गांधी सरकार ने अयोध्या के माध्यम से राजनीतिक समायोजन का प्रयास किया। 1986 में फैजाबाद जिला न्यायाधीश ने एक अधिवक्ता की याचिका पर विवादित परिसर का ताला खुलवा दिया और हिंदुओं को अंदर से दर्शन करने की अनुमति दे दी। इसी प्रक्रिया में तत्कालीन केंद्र सरकार ने अयोध्या में मंदिर के शिलान्यास की अनुमति भी दे दी। राजीव गांधी का प्रयास विफल रहा और वह चुनाव हार गए, क्योंकि उनकी कोशिश चुनावी राजनीति से प्रेरित थी,

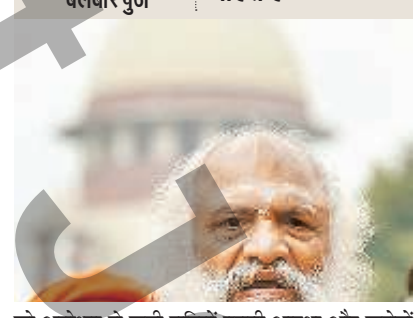

जो अयोध्या से जुड़ी सदियों पुरानी आस्था और करोड़ों लोगों की भव्य राम मंदिर के पुनर्निर्माण की मांग के समक्ष बौनी साबित हुई। फिर 6 दिसंबर, 1992 को 464 वर्ष पुरानी आहत भावना का विस्फोट हुआ और विवादित ढांचा गिरा दिया गया। रामजन्मभूमि मुक्ति के लिए 1528 से असंख्य रामभक्तों ने अपना बलिदान दिया है। 1735, 1751, 1756, 1757 और 1759 में हिंदुओं ने बार-बार रामजन्मभूमि को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया। 1767 में ऑस्ट्रियाई यात्री जोसेफ टिफ्फेनथेलर के अनुसार, 'मुगल शासकों के प्रतिबंध के बावजूद हिंदू, बाबरी ढांचे पर पूजा-अर्चना करते थे और रामनवमी उत्सव मनाते थे।'

क्या कारण है कि अयोध्या संबंधी मामला अब भी अदालत में लंबित है? इसका उत्तर कथित पंथनिरपेक्षकों की उस रुग्ण मानसिकता में छिपा है जो अपने क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थ के लिए इसे अनंतकाल तक विवादित रखना चाहते है। रामजन्मभूमि की लड़ाई आस्था से संबंधित है। यह कभी एक भूखंड के लिए या मस्जिद के विरुद्ध नहीं रही। यदि ऐसा होता तो 25 वर्ष पूर्व जब उग्र भीड़ ने विवादित ढांचे को गिराया तब वह अयोध्या या फैजाबाद की अन्य मस्जिदों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की। ढाई दशक पहले कारसेवकों ने अयोध्या में जिस ढांचे को जमींदोज किया उसे विदेशी आततायी ने इबादत के लिए नहीं, अपितु पराजित हिंदुओं को अपमानित करने हेतु स्थापित कराया था। बीसवीं शताब्दी के प्रसिद्ध ब्रितानी इतिहासकार आर्नोल्ड जोसेफ टॉयनबी के अनुसार, 'पोलैंड की राजधानी वारसॉ पर रूस के पहले कब्जे (1614-1915) के दौरान रूसियों ने शहर में एक चर्च की स्थापना की थी। इससे रूसी पोलैंडवासियों को स्पष्ट करना चाहते थे कि अब वे ही उनके स्वामी हैं। 1918 में स्वतंत्रता के पश्चात पोलैंड सरकार ने इस चर्च को गिरा दिया। बतौर टॉयनबी, 'मैं चर्च गिराने के लिए पोलैंड के सत्तातंत्र को दोष नहीं दूंगा, क्योंकि रूस द्वारा बनाया गया चर्च आस्था या मजहब से जुड़ा न होकर पोलैंडवासियों की राष्ट्रीय भावना को चोटिल करने से प्रेरित था।' टॉयनबी के अनुसार, 'रूसियों की भांति भारत में इस्लामी आक्रांताओं द्वारा स्थापित भवनों, मस्जिदों के निर्माण का मूल उद्देश्य भी हिंदुओं की भावना को आहत और उन्हें अपमानित करना था।' वह औरंगजेब राज में बनारस में दो और मथुरा में एक मस्जिद का उल्लेख करते हैं। उनके अनुसार, 'औरंगजेब को हिंदुओं को अपमानित और उनकी भावना को ठेस पहुंचाने हेतु उनके धार्मिक स्थलों को चिन्हित करने में महारथ हासिल थी।'

मध्यकाल में विदेशी आक्रांताओं द्वारा हिंदू मंदिरों को तोड़कर मस्जिदों की स्थापना का उद्देश्य राजनीतिक था। ऐसे में इन ऐतिहासिक अन्यायों का प्रतिकार और परिमार्जन केवल राजनीतिक रूप से संभव है, न कि कानूनी रूप से। स्वतंत्रता के बाद पहले गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में गुजरात में सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण इसकी मिसाल है। आस्था संबंधी जो मामले सदियों से अनसुलझे हों या जिनका ऐतिहासिक राजनीतिक आधार है उनके समाधान में न्यायिक प्रक्रिया बौनी नजर आई है? स्वतंत्रता पूर्व भारतीय नेतृत्व ने मुस्लिम लीग के मजहबी दवाब में देश के विभाजन को स्वीकार किया। क्या उस समय किसी न्यायालय ने इसकी रूपरेखा तैयार करने में कोई भूमिका निभाई थी? जनवरी 2015 में एक उर्दू अखबार के संपादक को 'शार्ली एब्दो' में प्रकाशित मोहम्मद साहब के विवादित कार्टून को दोबारा छापने पर गिरफ्तार किया था। उससे पहले सलमान रश्दी के उपन्यास 'सेटेनिक वर्सेस' और तसलीमा नसरीन की पुस्तक 'लज्जा' पर प्रतिबंध लगाया गया। इनमें क्या किसी सत्तातंत्र या प्रभावित पक्ष ने न्यायिक हस्तक्षेप की प्रतीक्षा की? रामजन्मभूमि मामले का निर्णायक हल विधायिका और शासन द्वारा ही संभव है, किंतु जब तक सिब्बल सरीखे कथित सेक्युलरिस्ट विद्यमान हैं तब तक करोड़ों लोगों को सदियों पुराने लंबित 'न्याय' के लिए और इंतजार करना पड़ सकता है।

(लेखक राज्यसभा के पूर्व सदस्य एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

स्वयं को जीतें

सृष्टि के आरंभ काल से ही प्रत्येक जीव में दूसरों पर शासन करने, दूसरे को जीतने की आकांक्षा पाई जाती है। संभवतः सत्ता आदमी की मूल प्रवृत्ति है। दूसरों को जय करने की इस कामना के चलते ही सर्वदा से युद्ध होते आए हैं। प्रारंभ में एक कबीला दूसरे कबीले पर, एक राज्य दूसरे राज्य पर और एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर अधिकार करने, उसे जीतने का उपक्रम करता रहा है। हम दूसरों को जय करने से पूर्व यदि खुद को जय कर लें तो सारे विवाद, लड़ाई-झगड़े स्वतः समाप्त हो जाएंगे। खुद को जीतने का अर्थ है, खुद पर नियंत्रण, लेकिन यह इतना सरल नहीं है, पर यह कार्य साधना के द्वारा आसानी से हो सकता है। भारतीय दर्शन में मन की चंचलता पर विपुल सामग्री है और इसको साधने के उपायों पर भी बहुत कुछ कहा गया है। देखा जाए तो गीता में भगवान श्रीकृष्ण इसी मन को साधने के लिए सखा अर्जुन से अनेक उपायों की चर्चा करते हैं। हमारा मन कभी इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं रहता कि कोई हम पर शासन करे या अधिकार जताए।

वर्तमान समय में और विशेष कर आधुनिक शिक्षा के प्रभाव से अपने घरों में हम बड़ों के आदेश-निर्देश को छोटों द्वारा अवज्ञा करते अक्सर देखते हैं। नई पीढ़ी का यह विद्रोह नया भी नहीं है। इतिहास पर दृष्टि डालें तो हम देखेंगे कि यह समस्या हर युग में रही है। दरअसल इसे नकारने में यह भावना अधिक काम करती है कि कोई नहीं चाहता कि कोई उस पर शासन चलाए। अब यहां पर फिर मन को साधने के लिए गीता की शरण में जाने की जरूरत महसूस होने लगती है। सारे झगड़े के मूल में यह मन ही है जो हमें स्वतंत्रतापूर्वक जीने का पाठ पढ़ाता रहता है। इसी के कारण हम किसी के शासन में रहना पसंद नहीं करते, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि किसी का नियंत्रण या मार्गदर्शन हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है। इसीलिए यह जरूरी है कि हम एक दूसरे का सम्मान करें, किसी पर शासन न चलाएं और सभी को परिवार से लेकर राष्ट्र तक, अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए आगे बढ़ने दें। इस प्रकार यदि हम स्वयं पर विजय पा लें तो दूसरों पर जय पाने की हमारी भावना तिरोहित हो सकती है। जीवन के लिए यह अति आवश्यक है। इसीलिए यदि जीवन में हमें अपने लिए तय लक्ष्यों को हासिल करना है तो इसे आत्मसात करना ही होगा।

डॉ. विश्राम

पाठकनामा

pathaknama@nda .jagran.com

विरासत संभालने की चुनौती

राहुल गांधी की राजनीतिक राह शीर्षक से लिखे अपने लेख में संजय गुप्त ने कांग्रेस की बढ़त के लिए एक स्पष्ट राजनीतिक सोच और ठोस वैकल्पिक नीतियों की जरूरत पर बल देते हुए एक सशक्त विपक्ष की जैसी अपेक्षा की है, वह तब तक संभव नहीं है जब तक कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र विकसित नहीं होगा। देश की यह राजनीतिक हकीकत है कि भाजपा के बढ़ते जनाधार से कई राज्यों में कांग्रेस पिछड़ गई है। अभी हाल में ही हुए उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव में प्रदेश की 16 मेयर सीटों में से 14 सीटों पर भाजपा की विजय ने यह साबित कर दिया है कि केंद्र सरकार की विकासवादी नीतियों की छाप राज्य में भी बरकरार है। ऐसे में कांग्रेस के रणनीतिकारों को मिल बैठकर यह विचार करने की जरूरत है कि कहीं कांग्रेस के सिमटते जनाधार के लिए परिवारवाद तो जिम्मेदार नहीं है? क्योंकि कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय राजनीतिक दल को संचालित करने के लिए जिस राजनीतिक कौशल की आवश्यकता है, कदाचित वह हुनर और तेजस्विता कांग्रेस के भावी अध्यक्ष के व्यक्तित्व में परिलक्षित नहीं हो रही है। इस दृष्टि से आज कांग्रेस के समक्ष यही सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है कि क्या राहुल गांधी विरासत में मिली अपनी इस जिम्मेदारी को संभाल पाएंगे?

pandeyvp1960@gmail.com

राजनीति की भाषा

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए निम्न कोटि की भाषा का इस्तेमाल कर नफरत का भाव दिखाया है। यह हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है? जहां नेतागण ही ऐसे बयानों से घिर रहे तो देश का क्या होगा? इनके जैसे पढ़े लिखे लोग आखिर जनता और समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? माना राजनीति में नेता लोग एक-दूसरे पर दोषारोपण करते ही रहते हैं, लेकिन इसका यह भी मतलब नहीं कि वे लोग गाली-गलौज पर उतर आएं। यह हमारे देश का दुर्भाग्य है, जहां आए दिन अभद्र भाषा का प्रयोग कर अपना गुस्सा व्यक्त किया जाता है। राजनीतिक दलों को चाहिए कि वह अपने विरोधियों के प्रति भी सम्मान का भाव रखें।

amandahri3012@gmail.com

राहुल की चुनौती

कांग्रेस के शीर्ष पद पर राहुल गांधी भले ही निर्विरोध चुन लिए गए हैं, लेकिन उन्हें बहुत सी चुनौतियों का सामना करना ही पड़ेगा। सबसे बड़ी चुनौती तो पार्टी की घटती छवि को सुधारने की है। भले ही कांग्रेस का शानदार इतिहास रहा हो, लेकिन आज वह विपक्षियों से विशेषकर भाजपा से पिछड़ गई है। पार्टी को नई ऊर्जा प्रदान करना उनके लिए चुनौती भरा काम है। राहुल गांधी जनाधार बढ़ाने में सफल हो गए तो वे कांग्रेस को जरूर उबार लेंगे।

mahesh_nenava@yahoo.com

अमर्यादित भाषा

गुजरात में चुनाव प्रचार मुद्दों से भटक गया है। विकास, सुशासन, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और राज्य स्तर के मुद्दों की जगह आरोपों ने ले लिया है। चुनावी रैलियों में केवल एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप हो रहे है। चुनाव प्रचार में अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। अगर दलों के एजेंडे में गरीबी, बेरोजगारी व भ्रष्टाचार खत्म करने की बात होती तो वे अमर्यादित भाषा की जगह इन्हीं मुद्दों पर बात करते और तथ्यों के साथ जनता को बताते कि हमने क्या किया और आगे हमारी क्या योजना है।

mkumar.sidhmukh@gmail.com

...तभी होगा नारी का सम्मान

आमिर खान की सुपरहिट फिल्म दंगल से बॉलीवुड में कदम रखने वाली कश्मीर की युवा अभिनेत्री जायरा वसीम के साथ फ्लाइट में छेड़छाड़ व हरियाणा में एक 5 साल की मासूम-सी बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना ने एक बार फिर नारी सुरक्षा को लेकर प्रश्न खड़े किए हैं। यह दोनों घटनाएं उसी सभ्य समाज में घटित हुई हैं, जहां यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः कहकर नारी का सम्मान किया जाता है। दरअसल यह छेड़छाड़ और दुष्कर्म की कोई पहली घटना भी नहीं है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की रिपोर्ट बताती है कि महिलाओं को सुरक्षा उपलब्ध कराने के बावजूद भी 2014 में प्रतिदिन 100 महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ और 364 महिलाएं यौनशोषण का शिकार हुई। गौर करने वाली बात है कि तमाम सुरक्षा के बाद महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं? क्योंकि हमारे देश में नारी अस्मिता से छेड़छाड़ करने वाले दरिंदे के खिलाफ कठोर सजा का प्रावधान नहीं है। हाल में जिस तरह मध्यप्रदेश सरकार ने 12 साल और उनसे कम उम्र की बच्चियों के दुष्कर्मियों को फांसी पर लटकाने का प्रस्ताव पारित किया, उसी तरह राष्ट्र स्तर पर भी हर आयु वर्ग की महिला की सुरक्षा को लेकर ऐसे प्रस्ताव पारित करने की आवश्यकता है। असल मायनों में नारी का सम्मान तभी होगा जब हम युवाओं के मन में यह कूट-कूट कर भर दें कि एक आदर्श समाज निर्माण के लिए महिलाओं का सम्मान करना अति आवश्यक है। इसके लिए स्कूलों में नैतिक शिक्षा को लागू करना होगा। इस के लिए यह भी आवश्यक है कि उन्हें अच्छा साहित्य पढ़ने को मिले। टीवी चैनलों पर अच्छे कार्यक्रम दिखाए जाएं जिससे युवाओं की नकारात्मक सोच में बदलाव हो। खेलकूद से भी बुरी प्रवृत्तियों का शमन किया जा सकता है। सामाजिक मूल्यों के विकास में लोक संस्कृति, इतिहास तथा साहित्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए इन को बढ़ावा देना भी जरूरी है।

devendrasuthar196@gmail.com

ट्वीट-ट्वीट

अगर भाजपा को जिस बैठक की खबर रही तो भला वह कैसे गुप्त बैठक हो सकती है। फिर भी अगर उसमें कुछ संदिग्ध